The Scheme was primarily launched to improve the lot of poor people by giving them loans for their self-employment and to deploy funds for economic rehabilitation of the rural areas and its implementation should be taken up on a continual basis. Government should also take the following steps so as to ensure that the Scheme achieved its primary aims :

1. Banks should be directed to formulate detailed guidelines and allocated at least 60 per cent of loans disbursed to people residing in rural areas.

2. There should be a continuous review and monitoring of the Scheme so that new targets may be laid down after the achievement of targets fixed earlier.

(vii) Steps for the re-surrection of scent and inscense sticks industry in Kannauj, Uttar Pradesh.

श्री छोटे सिंह यादव (कन्नौज): मान्यवर उत्तर प्रदेश का नगर कन्नौज सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारे संसार में इत्र और अगरबत्ती बनाने के लिए प्रसिद्ध रहा है। विश्व के मार्केट में कन्नौज के इत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। भारत सरकार को भारी मात्रा में व्यवसाय करने वाले लोग विदेशी मुद्रा कमा कर देते थे। वहां के लोग अपने घरों पर इत्र और अगर बत्ती बनाने के लिए छोटे-छोटे कारखाने लगाए थे और यह कुटीर उद्योग के रूप में चलता था। अधिकांश लोग इत्र बनाने वाली फसलों की खेती भी करते थे। उदाहरण के तौर पर मेंहदी, बेला, गुलाब, चमेली, खस आदि की, और इस खेती से अच्छी आय कमाते थे।

पिछले कुछ वर्षों से कन्नौज का यह व्यवसाय नष्ट हो रहा है, क्योंकि सरकार ने कभी इसकी विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। बिक्री कर, आयकर और उद्योग विभाग की अड़चनों के कारण यह व्यवसाय लगभग समाप्त हो रहा है। इत्र के फसलों की खेती करने वाले किसान पूरे तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। इस व्यवसाय में लगे सैंकड़ों कारीगर बेरोजगार हो गये और भारत सरकार को मिलने वाली विदेशी मुद्रा में ह्रास हुआ।

अत: मैं इस उल्लेख के द्वारा भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि कन्नौज के इत्र और अगरबत्ती उद्योग को फिर से बढ़ाने की जरूरत है। इस व्यवसाय पर लगे आयकर और बिक्री-कर को समाप्त करना चाहिये। इत्र और अगरबत्ती की खेती करने वाले किसानों को अनुदान मिलना चाहिये और सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिये। उद्योग विभाग को इस व्यवसाय में लगे कारीगरों को तकनीकी सहायता करनी चाहिए ताकि व्यवसाय बढ़ सके, हजारों लोगों को रोजगार मिले और भारत सरकार को मिलने वाली विदेशी मुद्रा में वृद्धि हो।

(viii) Need to ensure allotment of reserved seats in various University Courses to Scheduled Castes and Scheduled Tribes students

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों की बात तो खूब की जाती है, लेकिन वास्तविकता उसके विपरीत है। जब दिल्ली में इन समुदायों के छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है तो देश के अन्य भागों में क्या न्याय मिलेगा? नियमानुसार शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के लिये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिये 22.5 प्रतिशत सीट आरक्षित

[श्री राम विलास पासवान]

हैं, लेकिन योग्य छात्र उपलब्ध होने पर भी उनका नामांकन नहीं किया जाता।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय जो एक आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया, इस वर्ष एम० फिल एवं पी० एच० डी० से नामांकन हेतु सोशल साइंस में पद सुरक्षित थे। 100 से अधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र साक्षात्कार में सम्मिलित हुए, लेकिन सिर्फ 29 छात्रों को दाखिला दिया गया। लैंग्वेज में 17 सुरक्षित स्थानों पर सिर्फ 3 छात्रों का नामांकन किया गया जबकि 50 से अधिक छात्र योग्य थे। इंटर नेशनल स्टडीज में 37 सुरक्षित स्थान पर 23 छात्रों का नामांकन किया गया। लाइफ साइंस में 6 स्थान सुरक्षित थे, सिर्फ दो का नामांकन किया गया।

यही हालत एम० ए०, एम० एस० सी० के नामांकन में है।

दिल्ली विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय की स्थिति इससे भी बदतर है। नामांकन के अलावा कम छात्रवृत्ति मिलना, सभी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलना, छात्रावास में जगह नहीं मिलना, जातिगत आधार पर भेदभाव करना आदि अलग समस्याएं हैं।

अतः सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करे।

(ix) Need for reso ation of R. M. S. sorting section and enhancement of salary of E.D. Employees

DR. A. KALANIDHI (Madras Central) : Out of 265 Railway Mail Service Sorting Sections, 200 have been abolished already on the pretext of effecting savings in expenditure and quick delivery by air routes. Actually, in practice this has not led to any savings or quick delivery. But it has led to abnormal delay in the delivery of letters, etc. and unnecessary expenditure in keeping the personnel in reserve, without adequate employment. The opportunities of further employment are also sealed. The E.D. employees are starving for want of employment. They could neither earn here nor seek any other employment elsewhere. As our country is very vast and our villages are not even connected by bus routes, it is not fair to expect the P&T to use the air routes for delivering the postal articles, etc. Our system cannot be compared with the system that exists in United States of America. Only by maintaining these RMS Sorting sections the mail posted by public could be expected to reach its destination at least in a day or two. Now it takes four or five days. Government is, therefore, requested to restore these RMS Sorting Sections and pave the waw for the speedy delivery of Postal articles. The minimum salary to the E.D. employees in P&T should be at least Rs. 275/- p. m. and they should be regularized forthwith. Even an ordinary Mazdoor gets Rs. 15/- per day, whereas the E.D employees get much less for a day's working Government, as a model employer, should set things right, and lead the path of welfare State in our country.

MR DEPUTY-SPEAKER : Now we take up Legislative Business *viz* Constitution (Forty-seventh Amendment) Bill. Do you want to speak, Mrs. Ram Dulari Sihna.

14.00 hrs.

CONSTITUTION (FORTY-SEVENTH AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : I beg to move :

"That the Bill further to amend

*Published in the Gazette of India Extrardinary, Part II, Sec. 2, Dt. 22-8-1984.